संरक्षकः मां वैष्णो देवी
राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र

सुबह से शाम

PRN: MCN/111/2024-2026
RNI. No. MAHHIN/2008/28092

S.S. Media Group

तक की खबरें
मूल्य - 2₹



* वर्षः 19 * अंकः 22 * मुंबई, रविवार, 8 नवंबर से 14 नवंबर 2026 * संपादकः- एस.के.तिवारी * पेजः 4 Email Id - ssnews2008@gmail.com www.subahsesham.com

पेट्रोल में 30% से ज्यादा एथनॉल मिलावट का आरोप राहुल गांधी ने मोदी सरकार से मांगा जवाब

कर्नाटक के 14 नमूनों में से 11 में 20% से अधिक एथनॉल मिलने का दावा, इंडियन ऑयल ने आरोपों को बताया प्रक्रियागत जांच में अपुष्ट



संवाददाता

नई दिल्ली। कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित मानकों से अधिक एथनॉल मिलने के दावों के बाद ईंधन की गुणवत्ता को लेकर विवाद गहरा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने E20 पेट्रोल नीति पर केंद्र सरकार को घेरते हुए देशभर में बेचे जा रहे पेट्रोल में एथनॉल की वास्तविक मात्रा सार्वजनिक करने की मांग की है। हालांकि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इन दावों को निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत हुई जांच में अपुष्ट बताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल के नमूनों की जांच के नतीजों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सात जिलों से लिए गए 14 नमूनों में से 11 में एथनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई। उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, "E20 बना 420 जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी।"

IOCL और HPCL के नमूनों में अधिक एथनॉल का दावा

राहुल गांधी के अनुसार, जांच में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के नमूनों में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) के नमूनों में 30.5 प्रतिशत एथनॉल पाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम (BPCL), नायरा और शेल जैसी सरकारी एवं निजी तेल कंपनियों के नमूनों में एथनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक थी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि कंपनियों की अपनी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट में एथनॉल की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया।

वाहन मालिकों को नुकसान होने का आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि वाहन मालिक पेट्रोल की कीमत चुका रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों में निर्धारित मात्रा से अधिक एथनॉल डाला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इससे वाहनों की माइलेज प्रभावित हो सकती है और बार-बार खराब होने के कारण वाहन मालिकों को मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन में एथनॉल की वास्तविक मात्रा की जानकारी क्यों नहीं दी जाती और ग्राहकों को ईंधन चुनने का विकल्प क्यों नहीं मिलता। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा कि देश में पेट्रोल में वास्तव में कितना एथनॉल मिलाया जा रहा है और 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल पाए जाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बहस की चुनौती भी दी।

इंडियन ऑयल ने दावों को किया खारिज

दूसरी ओर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 'एक्स' पर जारी बयान में कहा कि कर्नाटक के कुछ पेट्रोल पंपों पर निर्धारित सीमा से अधिक एथनॉल मिलाए जाने के हालिया दावों की पुष्टि निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत की गई जांच से नहीं होती है। कंपनी के अनुसार, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 893 नमूनों की जांच की गई, जिनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे। कंपनी ने दावा किया कि सभी नमूनों में एथनॉल की मात्रा निर्धारित 19 से 21 प्रतिशत की सीमा के भीतर पाई गई। इंडियन ऑयल ने IOCL, BPCL और HPCL की ओर से कर्नाटक सरकार को संयुक्त और पारदर्शी जांच कराने का आग्रह किया है, ताकि तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके। कंपनी ने कहा कि वह ईंधन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उपभोक्ताओं से आधिकारिक स्रोतों की सत्यापित जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। इस मामले में राहुल गांधी के आरोपों और तेल कंपनियों के दावों के बीच पेट्रोल में एथनॉल की वास्तविक मात्रा को लेकर विवाद जारी है।

एसटी यात्रा में महिलाओं की रियायत के लिए एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता 1 जनवरी 2027 तक टली



संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) की बसों में महिलाओं को यात्रा के दौरान मिलने वाली रियायतों का लाभ उठाने के लिए एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करने के फैसले की समयसीमा 1 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी गई है। इससे महिलाओं को 7 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक स्मार्ट कार्ड के बिना भी यात्रा रियायतों का लाभ मिलता रहेगा। यह जानकारी शुक्रवार को परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने दी। सरकार के निर्देशानुसार यात्रा रियायतों को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए एसटी महामंडल ने एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड वितरण की प्रक्रिया शुरू की है। 1 अक्टूबर 2026 से महिला और वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के लिए यह कार्ड अनिवार्य किया गया था। अब तक लगभग 1 करोड़ 10 लाख कार्डों का पंजीकरण एवं वितरण किया जा चुका है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाओं का पंजीकरण अभी भी अधूरा होने की बात सामने आई है। सभी पात्र लाभार्थियों तक स्मार्ट कार्ड पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, यात्री संगठनों और ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के सहयोग से यह अभियान चलाया जाएगा। महामंडल ने 31 दिसंबर 2026 तक सभी महिला लाभार्थियों का 100 प्रतिशत पंजीकरण और कार्ड वितरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एसटी महामंडल की ओर से सभी महिलाओं से अपील की गई है कि वे समयसीमा के भीतर एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड के लिए अपना पंजीकरण पूरा कर लें।

मुंबई में धूल और निर्माण मलबे के खिलाफ BMC का विशेष अभियान अब तक 779 टन से अधिक C&D वेस्ट और 368 टन धूल एकत्रित



संवाददाता

मुंबई। मुंबई की वायु गुणवत्ता बनाए रखने तथा सड़कों पर धूल और निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे (C&D Waste) के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग द्वारा 28 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक विशेष सड़क सफाई और धूल नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 779.55 टन निर्माण एवं तोड़फोड़ का मलबा और 368.91 टन धूल एकत्रित की गई है।

26 वार्डों के 146 प्रमुख मार्गों पर सफाई अभियान

महानगर पालिका आयुक्त अश्विनी भिड़े के निर्देशानुसार, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) डॉ. विपिन शर्मा के मार्गदर्शन तथा उप आयुक्त (ठोस कचरा प्रबंधन) किरण दिघावकर के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। मुंबई की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए सड़क सफाई और धूल नियंत्रण के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत महानगरपालिका के 26 प्रशासनिक विभागों के 146 सड़कों पर सफाई की जा रही है। मुंबई के प्रमुख और व्यस्त यातायात मार्गों पर विशेष प्राथमिकता दी गई है। इनमें बांद्रा-कुर्ला कनेक्टर (BKC), सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड (SCLR), पूर्व एवं पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे, जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (JVLR), घाटकोपर-मानखुर्द मार्ग, स्वामी विवेकानंद मार्ग (एस.वी. रोड), लिंक रोड, कार्टर रोड और सायन-मानखुर्द मार्ग प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन प्रमुख मार्गों के अलावा विभिन्न प्रशासनिक विभागों के धूल प्रभावित रास्तों और क्षेत्रों में भी सफाई एवं धूल नियंत्रण कार्य किए जा रहे हैं।

सड़क की गहन सफाई, मिस्टिंग और पानी का छिड़काव

अभियान के तहत सड़कों की गहन सफाई, झाड़ू लगाने, स्क्रैपिंग, सड़क किनारे जमा धूल एवं गाद हटाने, डिवाइडर, फुटपाथ और कर्ब स्टोन की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। धूल प्रभावित स्थानों पर पानी का छिड़काव और मिस्टिंग की जा रही है। एकत्रित कचरे को तत्काल उठाकर उचित तरीके से निस्तारित किया जा रहा है। यांत्रिक सफाई के साथ-साथ सफाई कर्मचारियों के प्रत्यक्ष श्रम का भी उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से धूल प्रभावित क्षेत्रों में मिस्टिंग और आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव कर धूल को हवा में फैलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं।

966 सफाई कर्मचारी और 88 मशीनों की मदद

इस विशेष अभियान में अब तक 966 सफाई कर्मचारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों के साथ कुल 88 मशीनों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है। इनमें 16 जेसीबी, 19 डंपर, 19 बहुउद्देशीय मिस्टिंग मशीनें, 22 मैकेनिकल पावर स्वीपर, 5 वॉक-बिहाइंड ई-स्वीपर और 7 डिवाइडर सफाई मशीनें शामिल हैं। महानगर पालिका के अनुसार, अभियान के दौरान अब तक 368.911 टन धूल और 779.55 टन निर्माण एवं तोड़फोड़ का मलबा एकत्रित किया गया है। मुंबई में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और सड़कों को स्वच्छ रखने के लिए यह विशेष अभियान लगातार जारी है।

शरद पवार के 'सिल्वर ओक' पर सियासी हलचल तेज, मुलाकात करने पहुंचे पार्थ पवार

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। शरद पवार के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने निवास 'सिल्वर ओक' पहुंचने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के कई वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात करने के लिए सिल्वर ओक पहुंचे हैं। वहीं, सूत्रों के अनुसार अजित पवार गुट के नेता पार्थ पवार भी शरद पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। शरद पवार से मुलाकात के लिए शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेताओं जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख और शशिकांत शिंदे के सिल्वर ओक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। पार्थ पवार के भी मुलाकात के लिए पहुंचने से राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को और बल मिला है।

प्रफुल्ल पटेल की अस्पताल में मुलाकात के बाद बढ़ी चर्चा

कुछ दिन पहले अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने अस्पताल जाकर शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस गुटों के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। इस बीच अजित



पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि यदि अजित पवार जीवित होते, तो 12 फरवरी को ही दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस गुटों का विलय हो गया होता। तटकरे के अनुसार, अजित पवार ने उन्हें इस संबंध में जानकारी दी थी।

सिल्वर ओक पर बढ़ी राजनीतिक गतिविधियां

सुनील तटकरे के दावे, प्रफुल्ल पटेल की शरद पवार से मुलाकात और अब पार्थ पवार के सिल्वर ओक पहुंचने के घटनाक्रम के बाद दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस गुटों के विलय को लेकर राजनीतिक चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। हालांकि, दोनों गुटों के विलय को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। ऐसे में सिल्वर ओक पर हो रही मुलाकातों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद सड़क योजना के लिए 116 करोड़ रुपये जारी

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद सड़क योजना के तहत पूर्ण किए गए कार्यों के लिए राज्य रोजगार गारंटी योजना के पूरक कुशल अनुदान से 116 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है। रोजगार गारंटी योजना मंत्री भरत गोगावले के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सूखे की स्थिति और दिवाली के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों की खेती से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के कार्य समय पर पूरे करने के उद्देश्य से मंत्री भरत गोगावले ने संबंधित विभागों को निधि वितरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद योजना के तहत किए गए कार्यों के लिए निधि उपलब्ध कराई गई।

खेतों तक बारहमासी सड़क उपलब्ध कराने का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद सड़क योजना किसानों को उनके खेतों तक बारहमासी सड़क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इससे खेती की जुताई, कृषि कार्यों और खेतों से उपज को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी। वितरित किए गए 116



करोड़ रुपये के निधि से योजना के शेष कार्यों को गति मिलने की संभावना है।

ग्रामीण कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं पाणंद सड़कें

पाणंद सड़कें ग्रामीण कृषि व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा हैं। इनके माध्यम से किसान खेतों तक पहुंचने, दैनिक कृषि कार्य करने और कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। सूखे की परिस्थितियों में किसानों के साथ खड़े रहने के साथ ग्रामीण विकास कार्यों को भी जारी रखने की सरकार की भूमिका के तहत यह निधि वितरित की गई है। मंत्री भरत गोगावले ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी निधि उपलब्ध होते ही उसे तत्काल वितरित किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और दिवाली के अवसर पर किसानों को शुभकामनाएं भी दीं।

गोकुळ पर कब्जा करने का सरकार का कोई इरादा नहीं : मुख्यमंत्री फडणवीस

अध्यक्ष चुनाव में कोरम का पेच, दोनों गुट मिलकर निकालें रास्ता, नामांकन की नौबत टालने की अपील



संवाददाता

मुंबई। कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण अध्यक्ष का चुनाव अटका हुआ है। इस बीच, सरकार द्वारा सदस्यों को नामित कर गोकुळ पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश किए जाने के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का संस्था पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों गुट आपस में बैठकर समाधान निकालते हैं, तो सदस्यों के नामांकन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यह पूरी तरह वैधानिक मामला है और इसे राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है।

अध्यक्ष चुनाव में आखिर क्या है पेच?

गोकुळ के चुनाव के बाद दोनों गुटों में से किसी के पास भी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आवश्यक कोरम पूरा करने जितने मत नहीं हैं। ऐसे में यदि कोई एक गुट बैठक में उपस्थित नहीं होता है या बहिष्कार करता है, तो अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता। बैठक की तारीख निर्धारित होने के बावजूद एक गुट के सदस्य अनुपस्थित रहे, जिससे चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। मुख्यमंत्री फडणवीस के अनुसार, अदालत ने 10 तारीख को बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अदालत ने यह नहीं कहा था कि कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में कोरम के बिना ही चुनाव कराया जाए। इसलिए दोबारा चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

तीन बार बैठक विफल होने पर DDR के पास जाएंगे अधिकार

गोकुळ की कानूनी व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि लगातार तीन बार बैठक नहीं हो पाती है, तो संस्था के अधिकार जिला उपनिबंधक (DDR) के पास चले जाते हैं। इसके बाद निर्वाचित सदस्यों के पास ये अधिकार नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि बार-बार कोरम के अभाव में बैठक स्थगित होने की स्थिति में अंततः संस्था के अधिकार सरकार के पास जाने की परिस्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में जिला उपनिबंधक के माध्यम से आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरम पूरा करने के उद्देश्य से कुछ सदस्यों को नामित करने का अधिकार देने वाला कानून बनाया गया है। दोनों गुटों के पास अध्यक्ष (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री फडणवीस ने मराठवाडा वाटर ग्रिड परियोजना को गति देने के दिए निर्देश, सूखा मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम

जिला वार्षिक योजना के कम से कम 5% फंड से होगा चारा उत्पादन, चारा बैंक, हाइड्रोपोनिक्स और डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू होगी



संवाददाता

मुंबई। मराठवाड़ा में पानी की किल्लत की समस्या को स्थायी रूप से दूर कर इस क्षेत्र को सूखा मुक्त बनाने के उद्देश्य से मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना को गति देने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। उन्होंने परियोजना की प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तत्काल अपलोड कर केंद्र सरकार के आर्थिक कार्य विभाग को भेजने की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए।

मुंबई स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जिका) के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना की रूपरेखा तथा महाराष्ट्र और जापान के सहयोग से चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जिका की ओर से करीब 20 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बंद पाइपलाइन से आपस में जुड़ेंगे बांध

मराठवाड़ा में पानी के असमान वितरण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जल भंडारण वाले बांधों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बांधों तक बंद पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाना वाटर ग्रिड परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए दोहरी प्रवाह व्यवस्था विकसित की जाएगी। परियोजना के पहले चरण में छत्रपति संभाजीनगर, बीड, लातूर और धाराशिव जिलों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जायकवाड़ी, माजलगांव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा और निम्न मनार बांधों को आपस में जोड़ा जाएगा। लगभग 3,095 किलोमीटर लंबी मुख्य एवं द्वितीयक पाइपलाइन और 15 जलशुद्धिकरण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से करीब एक करोड़ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

आठ जिलों के लिए 25,056 करोड़ की परियोजना

पूरे मराठवाड़ा के आठ जिलों के लिए वाटर ग्रिड परियोजना की अनुमानित लागत करीब 25,056 करोड़ रुपये है। पहले चरण के लिए लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में जिका ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। लातूर और धाराशिव भूकंप संभावित क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में परियोजना के निर्माण में जापान की आधुनिक भूकंपरोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें डक्टाइल आयरन पाइप, आधुनिक पंपिंग व्यवस्था और SCADA प्रणाली शामिल होगी। (शेष पेज 2 पर)

संपादकीय

हिरासत के नाम पर मनमानी नहीं, संविधान सर्वोपरि

किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के बीच के समय को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कानून की प्रक्रिया के नाम पर किसी नागरिक की स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से सीमित करना संविधान की भावना के विपरीत है। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम भी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत के क्षण से शुरू होती है। यह फैसला पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि संवैधानिक प्रावधानों से बचने के लिए प्रक्रियात्मक अंतर का सहारा नहीं लिया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। इस अवधि में केवल न्यायालय तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक समय ही शामिल नहीं किया जाता। हिरासत और गिरफ्तारी के बीच कृत्रिम अंतर पैदा कर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक न्यायिक निगरानी से बाहर रखना कानून के उद्देश्य को कमजोर करता है। नशीले पदार्थों से संबंधित एक मामले में चार व्यक्तियों को हिरासत में लेने और उनकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के बीच लगभग 18 घंटे का अंतर सामने आया। इस अवधि के दौरान हिरासत में रखे जाने के स्पष्ट कारणों को लेकर सवाल उठे। ऐसी परिस्थितियां यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या गिरफ्तारी की प्रक्रिया को जानबूझकर विलंबित कर जांच एजेंसियों को अतिरिक्त समय और अधिकार देने का प्रयास किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो यह नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस को अपराध की जांच करने, अपराधियों को पकड़ने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। हिरासत के दौरान किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट या मानसिक प्रताड़ना के आरोप सामने आते रहे हैं। औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने में देरी ऐसी शिकायतों की जांच को भी जटिल बना सकती है।

इसलिए वास्तविक हिरासत के समय का सही रिकॉर्ड रखना और उसकी न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेटों को भी निर्देश दिया है कि वे हिरासत में लिए जाने के वास्तविक समय को दर्ज करें और स्वतंत्र रूप से जांच करें कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन हुआ है या नहीं। यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायिक निगरानी केवल दस्तावेजों पर दर्ज औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस की कार्रवाई कानून के अनुरूप हो और किसी नागरिक की स्वतंत्रता अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी संवैधानिक व्यवस्था भी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अवैध हिरासत के मामलों में यह एक प्रभावी कानूनी उपाय बना रहना चाहिए। जम्मू-कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में निवारक हिरासत को लेकर उठे सवाल इस बात की याद दिलाते हैं कि जब जवाबदेही कमजोर होती है, तब नागरिकों के अधिकार प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। यह समझना आवश्यक है कि अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

कानून का शासन तभी मजबूत होता है, जब पुलिस और जांच एजेंसियां भी कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर निर्दोष नागरिकों की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं किया जा सकता। किसी भी लोकतंत्र में पुलिस की शक्ति का आधार कानून होना चाहिए, न कि मनमानी। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश है। अब आवश्यकता है कि इसका पालन केवल कागजों पर नहीं, बल्कि व्यवहार में भी सुनिश्चित किया जाए। पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, हिरासत का सही समय दर्ज किया जाए और मजिस्ट्रेट वास्तविक परिस्थितियों की जांच करें। संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इस गारंटी की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में नागरिक की स्वतंत्रता कोई प्रशासनिक कृपा नहीं, बल्कि उसका संवैधानिक अधिकार है। अपराध नियंत्रण के नाम पर इस अधिकार को कमजोर करना स्वीकार्य नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट संदेश यही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं—न नागरिक और न ही कानून लागू करने वाली एजेंसी।

प्रदूषण के अंधकार में दीपावली की रोशनी कैसे मनाएं?



सौरभ वार्ष्णेय



आस्था, परंपरा और उत्सव के नाम पर क्या हम आने वाली पीढ़ियों की सांसों से समझौता कर सकते हैं? दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक,प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र भी है। यहां देश के कोने-कोने से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं। दिल्ली-एनसीआर ऐसा क्षेत्र है, जहां हर कोई बेहतर भविष्य, रोजगार और जीवन की संभावनाएं तलाशता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस शहर को लोग अपने सपनों का ठिकाना बनाना चाहते हैं, उसी शहर की हवा आज उनकी जिंदगी के लिए खतरा बनती जा रही है। प्रदूषण की मार ऐसी है कि खुले आसमान के नीचे सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर प्रदूषण के इस घुटन भरे माहौल में हम दीपावली का पर्व कैसे मनाएं?

दीपावली भारतीय संस्कृति और परंपरा का ऐसा पर्व है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व सदियों पुराना है। यह अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि चौदह वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्रीराम जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में अयोध्यावासियों सहित पूरे अखंड भारत ने घर-घर दीप जलाकर खुशियां मनाई थीं। तभी से दीपावली का पर्व प्रकाश और उल्लास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की जाती है लेकिन समय के साथ दीपावली मनाने के तौर-तरीकों में काफी बदलाव आया है। मिट्टी के दीपों, घरों की सजावट, पारिवारिक मेल-मिलाप और पारंपरिक मिठाइयों का स्थान धीरे-धीरे दिखावे और आतिशबाजी की प्रतिस्पर्धा ने ले लिया है। आसमान को रंग-बिरंगी रोशनी से भर देने की होड़ में हम यह भूल जाते हैं कि कुछ घंटों का हमारा मनोरंजन किसी दूसरे के लिए सांसों का संकट बन सकता है। हजारों की संख्या में छोड़े जाने वाले पटाखे वातावरण में जहरीले कण, धुआं और हानिकारक गैसें घोल देते हैं। इसका प्रभाव केवल दीपावली की रात तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पहले से प्रदूषित हवा की स्थिति को और गंभीर बना देता है। दिल्ली-एनसीआर की स्थिति इस लिहाज से विशेष चिंता का विषय है। यहां पहले ही वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, कूड़ा जलाने और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने जैसे अनेक कारणों से वायु प्रदूषण का दबाव बना रहता है। ऐसे में आतिशबाजी इस संकट को और बढ़ाने का काम करती है। इसका सबसे अधिक खामियाजा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भुगतना पड़ता है। कई मासूम बच्चे ऐसी हवा में सांस लेने को मजबूर होते हैं, जो उनके स्वस्थ बचपन और बेहतर भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। प्रदूषण केवल आंखों में जलन, खांसी या सांस फूलने तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से हृदय और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ता है।

विडंबना यह है कि हम एक ओर मां लक्ष्मी से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी ही गतिविधियों से जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति यानी स्वच्छ हवा को दूषित कर देते हैं। जिस दीपावली का उद्देश्य जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाना है, क्या उसे धुएं और जहरीली हवा के बीच मनाना उचित है? क्या कुछ मिनटों की आतिशबाजी उन लोगों की तकलीफ से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, जिन्हें प्रदूषण के कारण अस्पतालों का रुख करना पड़ता है?

यहां यह समझना भी जरूरी है कि दीपावली पर पटाखे न चलाने की अपील किसी धार्मिक परंपरा या आस्था के विरोध में नहीं है। भारतीय संस्कृति तो प्रकृति को पूजने और उसके संरक्षण का संदेश देती रही है। हमारे पर्व और त्योहार भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे में पर्यावरण की रक्षा करना हमारी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का ही हिस्सा होना चाहिए। भगवान श्रीराम के आदर्शों में मर्यादा, करुणा, त्याग और लोककल्याण का विशेष स्थान है। उनके आगमन की खुशी में मनाए जाने वाले पर्व पर यदि हम किसी दूसरे के जीवन को संकट में डालें, तो हमें अपनी उत्सव परंपरा के वास्तविक उद्देश्य पर विचार करना चाहिए।

सरकार और न्यायालय समय-समय पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाते रहे हैं। पटाखों की बिक्री, उनके इस्तेमाल और ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। लेकिन केवल सरकारी आदेशों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। जब तक नागरिक स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अधूरी रहेगी। यह भी जरूरी है कि नियमों का पालन केवल कागजों तक सीमित न रहे। प्रशासन को अवैध पटाखों की बिक्री और प्रतिबंधित आतिशबाजी पर प्रभावी निगरानी रखनी चाहिए। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी।

दीपावली की खुशी मनाने के लिए आतिशबाजी अनिवार्य नहीं है। हम मिट्टी के दीपक जलाकर, घरों को सजाकर, जरूरतमंद परिवारों की मदद करके, बच्चों को मिठाइयां बांटकर और परिवार के साथ समय बिताकर भी इस पर्व को यादगार बना सकते हैं। स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दीप खरीदना न केवल हमारी परंपरा को जीवित रखेगा, बल्कि उनके रोजगार को भी सहारा देगा। सामूहिक रूप से दीपोत्सव आयोजित करना और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना इस पर्व को और अधिक सार्थक बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना होगा। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा वातावरण देना चाहते हैं, जहां दीपावली के अगले दिन उन्हें स्वच्छ हवा के बजाय प्रदूषण की चादर मिले? क्या हम चाहते हैं कि त्योहारों की खुशी के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़े? यदि नहीं, तो बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। दीपावली अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने का पर्व है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल अपने घरों को ही नहीं, बल्कि अपने विचारों को भी रोशन करें। आतिशबाजी के शोर और धुएं से ऊपर उठकर जीवन, स्वास्थ्य और प्रकृति को प्राथमिकता दें। आखिर त्योहार तभी सार्थक है, जब उसकी खुशियां सभी के हिस्से में आएं। इस दीपावली संकल्प लें कि घर-आंगन में दीप जलेंगे, लेकिन किसी की सांसों में धुआं नहीं भरेंगे। क्योंकि असली दीपावली वही है, जिसमें रोशनी भी हो, खुशहाली भी हो और हर किसी के हिस्से में स्वच्छ हवा भी आए।

साप्ताहिक राशिफल

मेष राशि: इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन निवेश से पहले सोच-विचार करना जरूरी है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से अनुकूल रह सकता है। नौकरी में आपके कार्यों की सराहना होगी। व्यापार में पुराने संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता बढ़ेगी।

मिथुन राशि: इस सप्ताह आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। नौकरी में रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता और सूझबूझ से लाभ मिलेगा। व्यापारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन उधार देने से बचें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी दूर करने का अवसर मिलेगा।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों को इस सप्ताह आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम सकारात्मक रहेगा। व्यापार में किसी नए समझौते से पहले सभी शर्तों की जांच करें। परिवार में किसी सदस्य की सलाह उपयोगी साबित होगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। नौकरी में नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। व्यापार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

कन्या राशि: इस सप्ताह आपकी मेहनत और योजनाबद्ध कार्यशैली से सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। पुराने भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी। परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी। किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है।

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रगति और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभदायक सौदे होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नौकरी में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। परिवार में छोटी बातों को लेकर मतभेद संभव हैं। बातचीत से समस्याओं का समाधान निकालें। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर में उन्नति के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई परियोजना या जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में विस्तार की योजना सफल होने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निवेश के मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए सप्ताह मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। नौकरी में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। व्यापार में धीरे-धीरे लाभ बढ़ेगा। किसी पुराने आर्थिक मामले में राहत मिलने की संभावना है। परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई योजनाओं और रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी में आपके विचारों को महत्व मिलेगा। व्यापार में तकनीक और नए संपर्कों से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। किसी पुराने मित्र से सहयोग मिलने की संभावना है। परिवार में चल रही गलतफहमी दूर हो सकती है।

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभदायक समझौते होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

पेज 1 का शेष

मुख्यमंत्री फडणवीस ने...

औद्योगिक क्षेत्रों को भी मिलेगा स्थायी जलापूर्ति का लाभ

परियोजना के माध्यम से छत्रपति संभाजीनगर के ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन और वाळूज औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को स्थायी जलापूर्ति उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर करने के साथ औद्योगिक विकास को भी गति मिलने की संभावना है।

महाराष्ट्र-जापान सहयोग से AVGC क्षेत्र को बढ़ावा

एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र में महाराष्ट्र को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए जापानी कंपनियों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) के सहयोग से विभिन्न पहल की जा रही हैं। इसके तहत फरवरी में मुंबई में 'मंगा कारवां' आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पहल का स्वागत किया।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

बैठक में जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण सिंह परदेशी, जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव अमगोथू नाइक, 'मित्रा' के विभाग प्रमुख डॉ. संजय बेलसरे सहित भारत में जापान की महावाणिज्यदूत हितोमी सातो, जापान के वाणिज्यदूत केंजी ताकागी और जिका इंडिया कार्यालय के मुख्य प्रतिनिधि ताकुरो ताकेउची सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गोकुळ पर कब्जा करने...

चुनाव के लिए पर्याप्त मत नहीं होने के कारण यह वैधानिक पेच उत्पन्न हुआ है।

'गोकुळ पर कब्जा करने में सरकार की कोई रुचि नहीं'

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि गोकुळ पर राज्य सरकार कब्जा करना चाहती है, ऐसी धारणा गलत है। उन्होंने कहा कि गोकुळ का चुनाव लगभग पांच हजार मतदाताओं और एक जिले के कुछ तालुकों तक सीमित है। राज्य सरकार को इस चुनाव में विशेष रुचि नहीं है और न ही उसे इस तरह का कोई कदम उठाने की आवश्यकता है।

दोनों गुट मिलकर निकालें समाधान

फडणवीस ने दोनों गुटों से आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि दोनों पक्ष एक साथ बैठकर निर्णय लेते हैं और कोई वैधानिक अड़चन नहीं आती, तो सरकार को किसी भी सदस्य को नामित करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका केवल वैधानिक जिम्मेदारी निभाने तक सीमित है। दोनों गुटों के बीच सहमति बनने पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी।

राज्य की राजनीति पर चुनाव का कोई प्रभाव नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोकुळ एक अच्छी और महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसके चुनाव का राज्य की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार को इस चुनाव में विशेष रुचि नहीं है। इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। फडणवीस ने दोहराया कि दोनों गुट आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकालें। यदि वैधानिक पेच दूर हो जाता है, तो सरकार की ओर से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहेगी।

एल.आई.सी



भारतीय जीवन बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या समाधान हेतु संपर्क करें।

-भारत सिंह
मो. 9967255741

महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन प्रति के स्वीकृति पूर्व एहतियातन बरती जाने के बावजूद, उसमें अंतर्भूत बाते जांचना संभव नहीं है। ऐसी अंतर्भूत बातों के लिए सुबह से शाम तक की खबरे के अंतर्गत समाचारपत्र या प्रकाशनों में आनेवाली कंपनियां, संस्थाए या व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ हुए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए समाचार पत्र जिम्मेदार नहीं है।

वसई विरार शहर महानगरपालिका

प्रभाग समिती (बी) विरार पूर्व

मुख्य कार्यालय - विरार, दूरध्वनी - ९५२५० - २४०२१७९ / २४०३४४२ / २४०२५६३

जा. क्र. ववविशम/कर/२५२२/२०२६-२७ दि.०५/११/२६

जाहीर नोटीस

महाराष्ट्र मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४६९ अन्वये जाहीर नोटीस खालील मालमत्तेच्या हस्तांतरण संबंधाने वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी कार्यालय नालासोपारा येथे प्राप्त झालेल्या मालमत्ता धारकाच्या प्रकरण परत्वे नोटिसीनुसार सदर हस्तांतरण संदर्भात कोणत्याही हितसंबंधाने हरकत अगर आक्षेप असल्यास हि नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत हितसंबंधाच्या व हरकतीच्या लेखी पुराव्यासह वसई विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग समिती बी कार्यालय विभागीय कार्यालय विरार येथे लेखी स्वरूपात हरकत नोंदवावी अन्यतः करवसुलीच्या सोयीसाठी सदर हस्तांतरण करून महानगरपालिका दप्तरी याबाबतची नोंद घेतली जाईल.

अ. क्र.	मालमत्ता क्र.	पावती क्र.	ज्याचे नावे मालमत्ता आहे त्याचे म्हणजे मालमत्ता विकणाऱ्याचे नाव किंवा अभिहस्तांकन कर्त्याचे नाव	खरेदीदाराचे किंवा अभिहस्तांकन नाव
1	NL02/946/43	ASS/54373	शबनम इमरान सय्यद	ईम्तियाज खान S/O जब्बार खान
2	NL02/708/9	ASS/54378	दुर्गा कन्स्ट्रक्शन	हितेश जितेन्द्रकुमार जैन
3	NL01/179/19	ASS/50351	देवी सरदार सिंह	शायन गोस्वामी
4	NL01/44/29	ASS/51460	दिनेश के. कांचन	सुधाकर शंभूनाथ पांडेय / गुंजा सुधाकर पांडेय
5	NL05/335/46	ASS/46453	रॉबिन सन्तय	सुमित्रा संतोष बाईत
6	NL05/335/44	ASS/46452	समर गाजी	राजेंद्र जोगिंद मुळीक / जोत्स्ना जोगिंद मुळीक
7	NL07/411/8	ASS/46955	वैशाली ल खटावकर	मानसी महेंद्र मालगुनकर
8	NL04/154/16	ASS/46956	प्रविण काशीनाथ मोरे	अनीता रामधारी साहनी
9	NL01/231/12	ASS/40979	तयबुल इस्माईल मोल्ला	हसनैन मो. उबैद शेख
10	NL02/551/6	ASS/47467	नजमा खातून सेराजुद्दीन अन्सारी/ मोहम्मद सेराजुद्दीन अन्सारी	मोहम्मद आरीफ S/O कमरुद्दीन
11	NL02/502/28	ASS/51270	सुगंधा भीमराव मतिवडे	सय्यद जावेद सय्यद हमीद पटेल
12	NL05/144/3	ASS/49319	कल्पेश रोहिदास शिंदे	शशिकला पिंटू राजभर
13	NL02/1011/20	ASS/47475	आकाश उपाध्याय	रौशन खातून
14	NL04/411/25	ASS/48653	साईदुल रहमान शेख	जगन्नाथ सोनारतन पाल / बिजिया जगन्नाथ पाल
15	NL03/726/20	ASS/48652	फैयाज शेख	खिलारी रामहित यादव
16	NL02/408/39	ASS/51843	उषादेवी विनोदकुमार जोजेडिया	शुभम राजेश मिश्रा / राजेशकुमार लालचंद मिश्रा
17	NL02/297/40	ASS/51840	शिला चौहान	विकी राजू राय
18	NL01/248/24	ASS/51845	रमेश राजनाथ दुबे / मनोज राजनाथ दुबे	रेखा निलेशकुमार मिश्रा / निलेशकुमार राजेश मिश्रा
19	NL02/1006/3	ASS/51240	निजामुद्दीन अली रजा शेख	मोहम्मद सिद्दिकी अन्सारी
20	NL02/323/5	ASS/55395	मनोहर एस. कांबळे	दतात्रय गणपत दिघे / दिक्षा दतात्रय दिघे

सही/-
सहा.आयुक्त
प्रभाग समिती (बी) विरार पूर्व
वसई विरार शहर महानगरपालिका

सुबह से शाम
तक की खबरें

महाराष्ट्र शासन द्वारा विज्ञापन हेतु मान्य

महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षाओं का अंतिम टाइमटेबल जारी

12वीं की लिखित परीक्षा 8 फरवरी से, 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2027 से होगी शुरू

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का अंतिम समय-सारणी जारी कर दिया है। मंडल की ओर से लिखित परीक्षाओं के साथ ही प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाओं की तारीखें भी निर्धारित की गई हैं। इसके बाद अब विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नाशिक, लातूर और कोंकण सहित नौ विभागीय मंडलों के माध्यम से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

12वीं की परीक्षा 8 फरवरी से

मंडल द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 12वीं की लिखित परीक्षा 8 फरवरी 2027 से शुरू होगी। वहीं, 10वीं की लिखित परीक्षा 15 फरवरी 2027 से आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाएं फरवरी-मार्च 2027 के दौरान होंगी।

प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाओं की तारीखें तय



बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक तथा मौखिक परीक्षाओं की तारीखें भी निश्चित कर दी हैं।

12वीं की प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षाः 20 जनवरी 2027 से 6 फरवरी 2027 तक

10वीं की प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षाः 28 जनवरी 2027 से 13 फरवरी 2027 तक

आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा पूरा टाइमटेबल

परीक्षाओं के अंतिम कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आधिकारिक परिपत्र जारी किया है।

परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विषयवार परीक्षा की तारीखों और विस्तृत समय-सारणी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की तारीखें घोषित होने के बाद विद्यार्थियों को अब निर्धारित समय के अनुसार अपनी पढ़ाई और पुनरावृत्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

ठाणे की तालाबपाली झील में कूदने वाली 32 वर्षीय महिला को सुरक्षित बचाया



संवाददाता

ठाणे। ठाणे पश्चिम स्थित बोटिंग सेंटर और प्रिसिजन फिशरीज के पास तालाबपाली झील में शुक्रवार रात कथित तौर पर कूदने वाली 32 वर्षीय महिला को आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों ने सुरक्षित बचा लिया। महिला की पहचान रेशमा खंडारे के रूप में हुई है। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान महिला को कोई चोट नहीं आई। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के अनुसार, 6 नवंबर की रात करीब 9:22 बजे झील में महिला के कूदने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन अधिकारी वाई. एम. तडवी, आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान, आपदा प्रबंधन सेल के कर्मचारी और नौपाडा पुलिस के अधिकारी पिकअप वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

नाव की मदद से महिला को निकाला गया

मौके पर पहुंचते ही आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान किरण घोडे और राजेंद्र नगारे ने बचाव अभियान शुरू किया। जवानों ने नाव की मदद से झील में मौजूद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव अभियान के बाद महिला को आगे की सहायता के लिए नौपाडा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि घटना के दौरान महिला को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों की तत्परता और त्वरित कार्रवाई के चलते महिला को समय रहते सुरक्षित बचाया जा सका।

MPSC की गट-क संयुक्त परीक्षा में 21 नए संवर्ग शामिल, परीक्षा योजना में बड़ा बदलाव

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ने जारी किया शुद्धिपत्रक, मुख्य परीक्षा, पूर्व परीक्षा के परिणाम और संवर्गों के विकल्प संबंधी नियमों में भी संशोधन

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षा की परीक्षा योजना में बड़ा बदलाव किया है। आयोग की ओर से जारी शुद्धिपत्रक के अनुसार, परीक्षा योजना में 21 नए संवर्गों को शामिल किया गया है। इस संबंध में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की गई है। आयोग ने 20 मई 2026 को महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षा की परीक्षा योजना जारी की थी। उस समय योजना के परिच्छेद 1.1 में छह संवर्गों का समावेश किया गया था। अब सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मई 2026 के शासन निर्णय के अनुसार, गट-क के जिन संवर्गों के लिए आयोग को मांगपत्र प्राप्त हुए हैं, ऐसे 21 संवर्गों को परीक्षा योजना में शामिल किया गया है। इन संवर्गों की सूची परिशिष्ट क्रमांक 1 में दी गई है।

पूर्व परीक्षा के परिणाम तक नए संवर्गों को शामिल करने का प्रावधान

आयोग के अनुसार, समान शैक्षणिक योग्यता वाले अन्य संवर्गों के लिए यदि पूर्व परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक मांगपत्र प्राप्त होता है, तो उन संवर्गों को भी संबंधित परीक्षा योजना में शामिल माना जाएगा।

वर्तमान और नए शामिल किए गए संवर्गों के लिए आयु सीमा 20 मई 2026 को जारी परीक्षा योजना के परिच्छेद 3.2 के अनुसार लागू होगी। हालांकि, शासन की ओर से समय-समय पर जारी होने वाले निर्णयों के अनुसार इसमें बदलाव भी लागू रहेंगे।



पूर्व परीक्षा के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में संशोधन

आयोग ने पूर्व परीक्षा के परिणाम की प्रक्रिया में भी संशोधन किया है। सामान्य शैक्षणिक योग्यता वाले संवर्गों के लिए उम्मीदवारों द्वारा आवेदन में दिए गए विकल्प और भरे जाने वाले अनारक्षित तथा आरक्षित पदों की कुल संख्या के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित की जाएगी। सामान्य शैक्षणिक योग्यता वाले संवर्गों के लिए सामाईक पूर्व परीक्षा के अंकों के आधार पर एक संयुक्त परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं, विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता आवश्यक होने वाले संवर्गों के लिए अलग-अलग परिणाम जारी किए जाएंगे।

मुख्य परीक्षा के स्वरूप में भी बदलाव

गट-क सेवा के सामान्य शैक्षणिक योग्यता वाले प्रशासनिक संवर्गों के लिए निर्धारित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के अनुसार संयुक्त मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता वाले तथा नए शामिल किए गए संवर्गों के लिए अलग मुख्य परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। यदि एक से अधिक संवर्गों के लिए एक ही संयुक्त मुख्य परीक्षा आयोजित की जाती है, तो उम्मीदवारों से आवश्यकता के अनुसार संवर्ग अथवा सेवा का विकल्प और प्राथमिकता क्रम लिया जाएगा। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है।

आयोग की वेबसाइट पर मिलेगी आगे की जानकारी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा योजना की अन्य शर्तों में यदि कोई बदलाव किया जाता है, तो इसकी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

ठाणे की तर्ज पर अन्य महानगरपालिका अस्पतालों में भी होगी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी

बच्चों में सुनने की समस्या का जल्द पता लगाने और उपचार की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करेंगे एकनाथ शिंदे

संवाददाता

मुंबई। ठाणे महानगर पालिका की तर्ज पर राज्य की अन्य महानगरपालिकाओं के अस्पतालों में भी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के साथ बच्चों में सुनने की समस्या का जल्द पता लगाने (अर्ली डिटेक्शन) और उपचार की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की जाएगी। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी। मलबार हिल स्थित सरकारी आवास 'नंदनवन' में हृदय और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करा चुके बच्चों तथा उनके अभिभावकों के लिए आयोजित दिवाली स्नेह मिलन समारोह में उपमुख्यमंत्री शिंदे संबोधित कर रहे थे। शिवसेना वैद्यकीय सहायता कक्ष, डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन और आरोग्यदूत फाउंडेशन की ओर से संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।



बच्चों को नया जीवन देने वाले डॉक्टरों का सम्मान

कार्यक्रम में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करा चुके आदित्य ठोसर द्वारा लिखित पुस्तक 'माय वर्ल्ड ऑफ साउंड' का उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों विमोचन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को नया जीवन देने वाले डॉक्टरों और मीडिया प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और उनके बेहतर भविष्य के लिए ऐसी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। ठाणे महानगरपालिका अस्पताल में उपलब्ध कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा को राज्य के अन्य महानगरपालिका अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, टीवी9 मराठी के इनपुट एडिटर मोहन देशमुख, न्यूज18 लोकमत के संपादक मंदार फणसे, एबीपी माझा के संपादक राजीव खांडेकर, जी 24 तास के संपादक कमलेश सुतार, साम टीवी के संपादक निलेश खरे, जय महाराष्ट्र के संपादक प्रसाद काथे, एनडीटीवी मराठी के जितेंद्र दीक्षित, लोकशाही न्यूज की संचालक अंजनी नायडू, एबीपी माझा की संपादक सरिता कौशिक तथा उपमुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष के प्रमुख मंगेश चिवटे सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि, डॉक्टर, उपचार करा चुके बच्चों के अभिभावक और गणमान्य उपस्थित थे।

मुंबई के सफाई कर्मचारियों को मिलेगा मालिकाना हक वाला घर पंचशील नगर में नए कर्मचारी आवासों की चाबियां वितरित

संवाददाता

मुंबई। मुंबई के स्वच्छता कर्मचारियों को सेवा निवास के साथ मालिकाना हक वाले घर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शुक्रवार को पंचशील नगर, कुलाबा में आश्रय योजना कक्ष, चरण-2 के अंतर्गत नवनिर्मित कर्मचारी आवासों की चाबियां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों वितरित की गईं। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर, महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, नगरसेवक मकरंद नार्वेकर, हर्षिता नार्वेकर तथा महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि स्वच्छता कर्मचारी स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता किए बिना नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को सम्मानजनक और सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के सभी स्वच्छता कर्मचारियों को सेवा निवास के साथ मालिकाना हक वाले घर देने का निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इससे भविष्य में कर्मचारियों को अपने घर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि स्वच्छता कर्मचारियों के लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य और वाल्मीकि आवास योजना शुरू की गई है। सेवा निवास संबंधित कर्मचारी के स्थान पर उसके बेटे की नियुक्ति होने पर उसे हस्तांतरित किया जाएगा। वर्ष 2028 तक स्वच्छता कर्मचारियों को



सेवा निवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक से अब तक मुख्यतः निजी क्षेत्र की बड़ी इमारतें बनाई जाती थीं, लेकिन पहली बार महानगरपालिका की इमारत इस तकनीक से तैयार की गई है। आवास परिसर में सामूहिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। स्वच्छता कर्मचारियों के योग्यताधारी बच्चों को वर्ग-3 में नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने न्यायालयीन लड़ाई जीतकर लाडपागे समिति की सिफारिशें लागू की हैं। इसके अलावा ठेका, दैनिक वेतन और एवजदार पद्धति से काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन तथा आवश्यक सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वच्छता कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि जब मुंबई गहरी नींद में होती है, तब ये कर्मचारी सड़कों की सफाई कर शहरवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। कोविड महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने सेवा दी। गहन सफाई अभियान और बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति में भी कर्मचारी लगातार काम करते हैं। मुंबई का वास्तविक हीरो स्वच्छता कर्मचारी है। उन्होंने बताया कि मुंबई महानगर पालिका के 29 हजार स्वच्छता कर्मचारियों को सेवा आवास उपलब्ध कराने की योजना का पहला चरण शुरू हो गया है। मुंबई की 146 कर्मचारी बस्तियों का चरणबद्ध पुनर्विकास कर सभी कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण आवास दिए जाएंगे। इस परियोजना में पहले 150 वर्ग फुट के घरों के स्थान पर 300 वर्ग फुट के घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महानगरपालिका ने पहली बार प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक का उपयोग कर इन आवासों का निर्माण तेजी से किया है। विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर ने कहा कि मुंबई के 29 हजार स्वच्छता कर्मचारियों को घर उपलब्ध कराने के सपने की शुरुआत पंचशील नगर में 140 फ्लैटों की चाबी वितरण से हुई है। मुंबई को स्वच्छ और स्वस्थ रखने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।



गंजे सिर पर बाल उगाने का दावा करने वाला आयुर्वेदिक हेयर ऑयल FDA के रडार पर, 50.35 लाख रुपये का माल जब्त

संवाददाता

मुंबई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विज्ञापन देकर पूरी तरह गंजे सिर पर भी बाल उगाने का दावा करने वाला आयुर्वेदिक हेयर ऑयल महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई के घेरे में आ गया है। शुक्रवार को एफ़डीए से मिली जानकारी के अनुसार FDA के नासिक विभाग ने इस उत्पाद की 5,040 बोतलें जब्त की हैं, जिनकी कुल कीमत 50.35 लाख रुपये बताई गई है। जांच में उत्पाद के लेबल पर निर्माता का नाम, पता और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर नहीं मिलने से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

सोशल मीडिया पर गंजेपन के इलाज का दावा

'VS हेयर ग्रोथ ऑयल' नामक इस उत्पाद का इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रचार किया जा रहा था। विज्ञापनों में दावा किया गया था कि यह तेल गंजे सिर पर दोबारा बाल उगाने और बालों की वृद्धि में मदद कर सकता है। 100 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल पर 999 रुपये की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) अंकित थी।

नासिक के सैलून पर FDA की छापेमारी







उत्पाद के ऑनलाइन विज्ञापन और बिक्री को लेकर मिली गुप्त सूचना के आधार पर FDA अधिकारियों ने 5 नवंबर को नासिक के कॉलेज रोड स्थित 'M/s V. S. न्यू फैशन ज़ोन' पर छापा मारा। यह प्रतिष्ठान ब्यूटी सैलून और इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान के रूप में संचालित होता है। जांच के दौरान अधिकारियों को उत्पाद के लेबल पर केवल मार्केटर का नाम 'M/s V. S. न्यू फैशन ज़ोन, नासिक', बैच नंबर, निर्माण तिथि और कीमत दर्ज मिली। हालांकि, उत्पाद का वास्तविक निर्माता कौन है, इसका उल्लेख नहीं था। साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर भी गायब था।

बिना लाइसेंस बिक्री का आरोप, जांच जारी

FDA ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत कार्रवाई करते हुए तेल की 5,040 बोतलों का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि सैलून के मालिक योगेश भगत के पास इस उत्पाद के निर्माण के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अथवा आवश्यक कानूनी अनुमति नहीं थी। जब्त उत्पाद के नमूने जांच और विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं। FDA अब तेल के वास्तविक निर्माता की पहचान करने में जुटी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर आकर्षक दावों के जरिए बेचे जा रहे ऐसे उत्पादों की वैधता और सुरक्षा को लेकर इस कार्रवाई ने सवाल खड़े कर दिए हैं।

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का संगठनात्मक मंथन तेज: गोरखपुर की 62 सीटों पर जीत का लक्ष्य

नाराज कार्यकर्ताओं और उपेक्षित नेताओं को साधने की कवायद पुराने-नए चेहरों के बीच समन्वय बनाने पर जोर



संवाददाता

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन से मिले फीडबैक के आधार पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के दौरे के दौरान गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों के साथ संगठन की जमीनी स्थिति का आकलन किया गया।

पार्टी नेतृत्व ने पुराने और नए नेताओं से संवाद कर संगठन के भीतर असंतोष, उपेक्षित नेताओं की स्थिति तथा कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारणों को समझने का प्रयास किया। भाजपा की रणनीति पुराने नेताओं को फिर सक्रिय करने, नए चेहरों के साथ तालमेल बढ़ाने और परंपरागत मतदाताओं का भरोसा कायम रखने पर केंद्रित है। संगठनात्मक बैठकों के जरिए उन कमियों की पहचान की जा रही है, जो आगामी चुनाव में पार्टी की तैयारियों को प्रभावित कर सकती हैं। वरिष्ठ पत्रकार मुमताज खान के मुताबिक, भाजपा का लगातार स्थानीय स्तर पर मंथन करना क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति उसकी गंभीरता को दर्शाता है। बैठकों के माध्यम से यह जानने की कोशिश हो रही है कि संगठन में कहां कमजोरियां हैं और किन नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है।

नौकरशाही के प्रभाव से कार्यकर्ताओं में उपेक्षा की भावना

गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अमित कुमार उपाध्याय का मानना है कि सरकार में नौकरशाही का प्रभाव बढ़ने से कार्यकर्ताओं में उपेक्षा की भावना पैदा होती है। इससे राजनीतिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारियों के दौरान पुराने और नए नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करना जरूरी है। केवल संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय करना होगा, जो किसी कारण से मुख्यधारा से दूर हो गए हैं।

युवा वर्ग की नाराजगी भी भाजपा के लिए चुनौती

युवा वर्ग भी विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक नेतृत्व के सामने युवाओं की अपेक्षाओं को सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की चुनौती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी युवाओं के विचारों और अपेक्षाओं को सुनने पर जोर दे चुके हैं। सरकार और संगठन के स्तर पर अब इन मुद्दों पर सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना और संगठन को मजबूत बनाना भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल है।

परंपरागत समर्थकों का भरोसा बनाए रखना अहम

वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परंपरागत समर्थक वर्गों का भरोसा बनाए रखने की है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामने आई नाराजगी भी पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में नियमों की समीक्षा के लिए समिति गठित करने पर विचार का आश्वासन इसी दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लंबे समय से उपेक्षित नेताओं की बात सुनना और उन्हें दोबारा जिम्मेदारी देकर सक्रिय करना संगठन को मजबूती प्रदान कर सकता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी आने वाले दिनों में संगठन और सरकार के स्तर पर और कदम उठा सकती है।

सभी 62 सीटों पर जीत का लक्ष्य

भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य गोरखपुर क्षेत्र की सभी 62 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने का संदेश दिया है। इसी क्रम में जिलों में संगठनात्मक गतिविधियां तेज की जा रही हैं। पार्टी का जोर संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका मजबूत करने और उन्हें आगामी चुनावी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने पर है।

बिग बॉस 20 में स्काउट OP की लव लाइफ पर संकट? गर्लफ्रेंड काश्वी के लाइव स्ट्रीम से ब्रेकअप की अटकलें तेज

संवाददाता

लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 'बिग बॉस 20' में इन दिनों कंटेस्टेंट तन्मय सिंह उर्फ स्काउट OP की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में है। शो में उनकी लव गिल के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच उनकी गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी के एक लाइव स्ट्रीम ने दोनों के रिश्ते को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है। हाल ही में काश्वी ने लाइव स्ट्रीम के दौरान स्काउट OP के प्रशंसकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दर्शकों से बिग बॉस को केवल एक रियलिटी शो की तरह देखने और कंटेस्टेंट्स की निजी जिंदगी में दखल न देने की अपील की। उनकी कुछ टिप्पणियों को सोशल मीडिया यूजर्स ने रिश्ते में तनाव के संकेत के तौर पर देखा।

'पांच साल ही तो थे'...

लाइव स्ट्रीम के दौरान काश्वी ने कहा, "5 साल ही तो थे, औरों ने तो अगर आपको पता है तो पता है।" इस टिप्पणी के बाद फैंस के बीच उनके और स्काउट OP के रिश्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई। काश्वी ने अपनी स्थिति पर बात करते हुए कहा कि वह पहले कभी ऐसी परिस्थिति से नहीं गुजरी हैं और हर चीज को एक-एक दिन के हिसाब से समझने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रियलिटी शो में जितनी ज्यादा ध्रुवीकृत परिस्थितियां होंगी, दर्शकों की प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक



होगी और लोग उतनी ही ज्यादा चर्चा करेंगे। उन्होंने साफ किया कि वह मौजूदा विवाद के बीच शांत रहने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही, उन्होंने इनसिक्योरिटी से जुड़ी बहस में पड़ने या इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने से भी इनकार किया। काश्वी ने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से स्काउट OP के फैंस के लिए जितना संभव था, उतना किया है और अपने समर्थकों से साथ बनाए रखने की अपील की।

'आखिरी एक्ट और आखिरी डांस' बयान ने बढ़ाई चर्चा

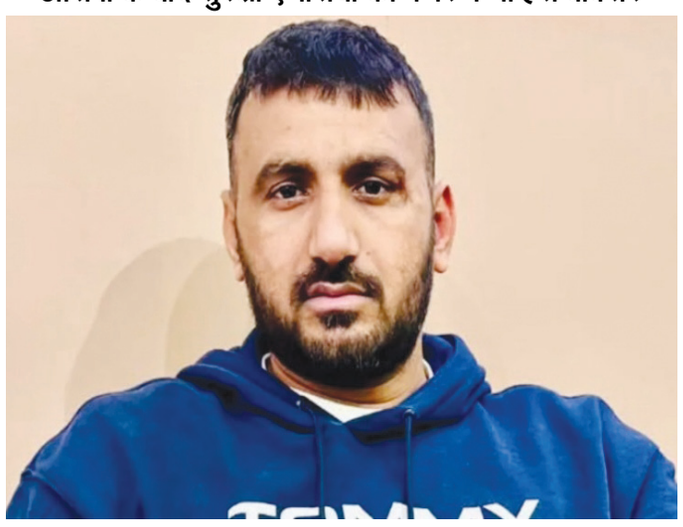
लाइव स्ट्रीम के अंत में काश्वी ने कहा- सच कहूं तो ये मेरे लिए आखिरी एक्ट और आखिरी डांस है। लेकिन इस बारे में बात करना दो लोगों के बीच है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर स्काउट OP और काश्वी के संभावित ब्रेकअप की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि, काश्वी ने सीधे तौर पर रिश्ते के खत्म होने का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में ब्रेकअप की खबरों को फिलहाल अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

लव गिल के साथ स्काउट की नजदीकियां बनीं चर्चा का विषय

काश्वी हीरानंदानी और स्काउट OP पिछले करीब पांच साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन 'बिग बॉस 20' में स्काउट की लव गिल के साथ बढ़ती नजदीकियों ने उनके रिश्ते को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, स्काउट और लव अपने रिश्ते को भाई-बहन जैसा बताते हैं, लेकिन दोनों का लगातार साथ समय बिताना दर्शकों के बीच सवाल खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे पर काश्वी ने 'वीकेंड का वार' के दौरान स्काउट से सीधे सवाल किए थे और लव के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों पर नाराजगी जाहिर की थी। बाद में काश्वी ने लव को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका सवाल केवल स्काउट के व्यवहार को लेकर था। इसके बावजूद शो में स्काउट और लव की नजदीकियां लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। फिलहाल काश्वी के लाइव स्ट्रीम के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने के लिए स्काउट OP या काश्वी की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

अमेरिका में हिरासत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर हैरी बॉक्सर, बॉलीवुड हस्तियों को दे चुका है धमकियां

रोहित शेट्टी के आवास पर गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने और सलमान खान के साथ काम करने वाले कलाकारों को धमकाने के आरोपों के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था हैरी बॉक्सर



संवाददाता

नई दिल्ली। अमेरिकी अधिकारियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, हैरी बॉक्सर अमेरिका से गैंग की आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था। हालांकि, उसकी हिरासत से जुड़े आधिकारिक विवरण सामने आने का इंतजार है। हैरी बॉक्सर उस समय सुर्खियों में आया था, जब उसने मुंबई में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के आवास के बाहर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी।

इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो संदेशों के जरिए बॉलीवुड की कई हस्तियों को धमकियां देने के आरोप भी उस पर लगे। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और धमकी देने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं।

बॉक्सिंग से अपराध की दुनिया तक

हैरी बॉक्सर का असली नाम हरि चंद जाट बताया जाता है। वह राजस्थान के अलवर जिले के नारायणपुर का रहने वाला है। बताया जाता है कि उसने कभी बॉक्सिंग का प्रशिक्षण लिया था और जयपुर में कोच के तौर पर भी काम किया था। बाद में उसका नाम विभिन्न आपराधिक मामलों में सामने आया और वह कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया। पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार, हैरी बॉक्सर वर्ष 2022 से फरार था। उसके अमेरिका में रहने की आशंका जताई जा रही थी। राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में उस पर रंगदारी, लूटपाट तथा हत्या के प्रयास जैसे मामलों में संलिप्त होने के आरोप हैं। जांच एजेंसियां उसे विदेश से गैंग की गतिविधियां संचालित करने वाले प्रमुख लोगों में शामिल मानती रही हैं।

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के बाद भी आया था नाम

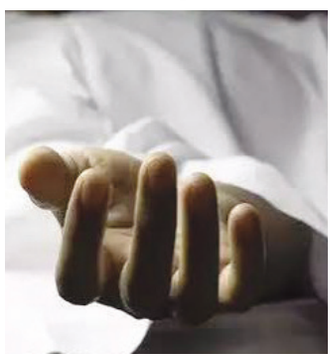
अगस्त 2025 में कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के बाद एक कथित ऑडियो संदेश सामने आया था। इसमें हैरी बॉक्सर द्वारा बॉलीवुड हस्तियों को अभिनेता सलमान खान के साथ काम करने पर निशाना बनाने की धमकी दिए जाने का दावा किया गया था। हैरी बॉक्सर का नाम अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध नेटवर्क और गैंगों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में भी चर्चा में है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उसकी हिरासत को लेकर आगे की कार्रवाई और भारत में संभावित कानूनी प्रक्रिया पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है।

कानपुर में पांच दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा 82 वर्षीय डॉक्टर का शव

संवाददाता

कानपुर, उत्तर प्रदेश। पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 82 वर्षीय डॉक्टर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव का पांच दिन पुराना शव बिस्तर पर पड़ा मिला। उनके साथ रहने वाला मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटा पिता की मौत से अनजान शव के पास ही बैठा रहा। फ्लैट से तेज दुर्गंध आने पर शादीशुदा बेटी और नाती वहां पहुंचे, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल डॉक्टर की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है।

प्रसाद देने पहुंची बेटी और नाती, अंदर का दृश्य देख रह गए स्तब्ध



जानकारी के मुताबिक, रतनपुर के अमन इन्क्लेव स्थित फ्लैट नंबर ए-304 में डॉक्टर प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव अपने बेटे विजय श्रीवास्तव के साथ रहते थे। उनकी तीन बेटियां अर्चना, भावना और प्रीति हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। अर्चना के बेटे अनमोल ने बताया कि उसने हाल ही में नई कार खरीदी थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद वह अपनी मां के साथ नाना के घर प्रसाद देने पहुंचा। फ्लैट में प्रवेश करते ही उन्हें तेज दुर्गंध महसूस हुई।

जब वे अंदर गए तो डॉक्टर प्रेम प्रकाश का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। वहीं, उनके बेटे विजय पास में ही बैठे थे। पिता की मौत से अनजान बेटे को देखकर परिजन स्तब्ध रह गए। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि डॉक्टर के बेटे को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। घटना के सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव, रामलला के दर्शन कर संतों से लेंगे आशीर्वाद

12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव, रामलला के दर्शन कर संतों से लेंगे आशीर्वाद



संवाददाता

लखनऊ, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी में पूजा-अर्चना करेंगे। सपा नेता एवं पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे की तारीख की जानकारी दी है। पवन पांडे के मुताबिक, अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव, बेटा और बेटी भी अयोध्या पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि सपा प्रमुख का यह दौरा पूरी तरह धार्मिक होगा। अखिलेश यादव अयोध्या में पूरा दिन बिताएंगे और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे अखिलेश

अयोध्या प्रवास के दौरान अखिलेश यादव सबसे पहले राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद वह हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी की पूजा-अर्चना करेंगे। पूर्व मंत्री पवन पांडे के अनुसार, सपा प्रमुख साधु-संतों और महंतों से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव अलग-अलग मठों में जाकर संतों का आशीर्वाद ले सकते हैं। इस दौरान संतों के साथ प्रसाद ग्रहण करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। उनका पूरा दिन धार्मिक गतिविधियों के बीच बीतने की संभावना है।

मंदिर में चोरी के मामले पर भी करेंगे प्रार्थना

पूर्व मंत्री पवन पांडे ने बातचीत के दौरान राम मंदिर में चोरी के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव रामलला और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तथा मंदिर में चोरी करने वालों के खिलाफ न्याय की विनती करेंगे।

सियासी लिहाज से भी अहम होगा अयोध्या दौरा

22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला अवसर होगा, जब अखिलेश यादव राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। इससे पहले भाजपा नेता रामलला के दर्शन नहीं करने को लेकर सपा प्रमुख पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में 12 दिसंबर को प्रस्तावित अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परिवार के साथ रामलला के दर्शन और संतों से मुलाकात के कार्यक्रम पर राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।

मुगलसराय में दर्दनाक सड़क हादसा: सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, मामा-भांजे की मौत

जलीलपुर गांव के पास भोर में हुआ हादसा, वाराणसी ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया

संवाददाता

चंदौली, उत्तर प्रदेश। मुगलसराय थाना क्षेत्र के जलीलपुर गांव स्थित घंटावीर बाबा मंदिर के पास शनिवार भोर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर में पीछे से स्कूटी टकराने से मामा-भांजे की मौत हो गई। दोनों पड़ाव चौराहे से मुगलसराय की ओर जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों को वाराणसी के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान उस्मान (32), पुत्र इस्लाम, निवासी दुल्हीपुर मुगलसराय और उनके मामा जुबैर (47), निवासी रायबरेली के रूप में हुई है।

सजावटी खंभे लगाने के काम में लगा था ट्रैक्टर

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब चार बजे पुलिस की पीआरबी टीम को जलीलपुर गांव के पास सड़क हादसे की सूचना मिली। पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे तो सड़क किनारे बिजली के सजावटी खंभे लगाने के काम में लगा एक ट्रैक्टर खड़ा मिला। इसी दौरान पड़ाव की तरफ से आ रही स्कूटी पीछे से ट्रैक्टर में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार दोनों लोग सड़क पर गिर पड़े। उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद घटनास्थल पर



अफरा-तफरी मच गई।

अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत

पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तत्काल पास के लतीफ अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों ने दोनों का परीक्षण किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मुगलसराय थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बताया कि दोनों शवों को आवश्यक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है।

सुकेश चंद्रशेखर से पहली मुलाकात पर नोरा फतेही का बड़ा खुलासा, चेन्नई कार्यक्रम में कार गिफ्ट करने की हुई थी पेशकश

संवाददाता

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही एक बार फिर कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के रंगदारी मामले को लेकर चर्चा में हैं। शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को नोरा फतेही ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉल से जुड़ी अपनी पहली मुलाकात के बारे में कई अहम जानकारियां दीं। नोरा के बयान के मुताबिक, दिसंबर 2020 में चेन्नई में आयोजित एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात लीना पॉल से हुई थी। इसी मुलाकात के बाद लीना ने फोन पर अपने पति सुकेश चंद्रशेखर से नोरा की बात कराई। बातचीत के दौरान अभिनेत्री को एक लग्जरी कार उपहार में देने की पेशकश भी की गई थी।

चेन्नई के चैरिटी कार्यक्रम में हुई थी पहली मुलाकात

नोरा फतेही ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2020 में उन्हें चेन्नई में एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए बुक किया गया था। कार्यक्रम की आयोजक लीना पॉल थीं, जिन्होंने एक्सीड एंटरटेनमेंट नामक एजेंसी के माध्यम से नोरा को आमंत्रित किया था। अभिनेत्री के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान जब वह तैयार हो रही थीं, तब उनकी टीम ने उन्हें बताया कि लीना अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनसे मिलना चाहती हैं। इसके बाद लीना कुछ लोगों और दो वीडियोग्राफरों के साथ उनके कमरे में पहुंचीं। उनके साथ कुछ उपहार भी थे। नोरा ने बताया कि लीना ने अपना



परिचय नेल आर्टिस्ट्री सैलून की मालिक के रूप में दिया था। मुलाकात के दौरान लीना ने कहा कि उनके पति उनसे बात करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर को फोन किया और स्पीकर पर बातचीत कराई।

फोन पर सुकेश ने खुद को बताया नोरा का प्रशंसक

नोरा के बयान के अनुसार, फोन पर सुकेश ने कार्यक्रम में आने के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि वे उनके बड़े प्रशंसक हैं। उसने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजि

त करने की इच्छा जताई। इसी बातचीत के दौरान लीना पॉल ने नोरा को कार उपहार में देने की बात कही। सुकेश ने भी अभिनेत्री से कार को उपहार के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया था। अदालत में दिए गए इस बयान के बाद सुकेश और बॉलीवुड हस्तियों से जुड़े महंगे उपहारों का मामला फिर चर्चा में आ गया है।

कार्यक्रम के लिए नहीं मिला था पारिश्रमिक

नोरा फतेही ने अदालत को बताया कि चेन्नई के चैरिटी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया था। हालांकि, आयोजकों की ओर से उनके आने-जाने का खर्च, स्टाफ का खर्च और हेयर-मेकअप आर्टिस्ट की फीस का भुगतान किया गया था। उनके ठहरने के लिए एक रात पांच सितारा होटल की व्यवस्था भी की गई थी। अभिनेत्री ने बताया कि उस समय टी-सीरीज उनकी नियोक्ता कंपनी थी और एक्सीड एंटरटेनमेंट की टीम ने कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संभाली थीं। कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और डांस प्रतियोगिता को जज भी किया था।

200 करोड़ रुपये की रंगदारी का मामला क्या है?

यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की रंगदारी का है। आरोप है कि सुकेश ने दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की वसूली की थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले की जांच की। जांच के दौरान नोरा फतेही से भी सुकेश और लीना पॉल के साथ उनके संपर्क को लेकर पूछताछ की गई थी। बाद में उन्हें अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया।

प्रकाशक, मुद्रक, मालिक व संपादक सुनील कुमार हरिशंकर तिवारी द्वारा बच्ची देवी कॉपरेटीव सोसायटी, शांतिलाल कंपाउंड, गोलीबार रोड़, खार (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५५ से प्रकाशित व सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट नं. ०४, ग्राउंड फ्लोर. एन.के.इंडस्ट्रीयल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नियर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं ०२, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई-४०००६३ से मुद्रित। किसी भी खबरो के चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत संपादक जिम्मेदार। किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र मुंबई।
संपादकीय कार्यालय- एस.एस.मीडिया ग्रुप, ब्रमदीन शर्मा चॉल, जवाहर नगर, साईबाबा रोड, खार (पूर्व), मुंबई - ४०००५१, संपादकः- एस.के.तिवारी. E-mail:- ssnews2008@gmail.com, RNI. No. MAHHIN/2008/28092, Mob. 8898271111
वसई-विरार संपर्क कार्यालयः गाला नं ४, जीवदानी चाल, साई नगर, गोराई नाका, नालासोपारा (पूर्व) पालघर. सहायक संपादकः राजकिशोर तिवारी, मो. 8898771152